विकास, उद्योग और टैक्स के लिए प्रदेश का डिजिटल सर्वे

वार्ड से लेकर गांव की गली तक का ड्रोन सर्वे कर नक्शा तैयार होगा

अमर उजाला ब्यूरो

आपदा के समय प्रदेश के किसी भी कोने को लाइव कंट्रोल किया जा सकेगा

लखनऊ। प्रदेश के प्रत्येक इलाके में समान बुनियादी विकास, औद्योगिक विकास, परिवार सर्वे के साथ-साथ वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए डिजिटल सर्वे किया जाएगा। वार्ड से लेकर गांव तक की गली का ड्रोन सर्वे कर उनका नक्शा तैयार किया जाएगा।

प्राकृतिक रूप से समृद्ध इलाकों का डिजिटल ग्राफ अलग से बनेगा। आपदा के समय प्रदेश के किसी भी कोने को लाइव कंट्रोल किया जा सकेगा। कहां जमीन खाली है और कहां कब्जा है, ये एक क्लिक पर मिल जाएगा। इसके लिए श्रीट्रान इंडिया ने आवेदन मांगे हैं। 24 अक्तूबर को अंतिम मुहर लग जाएगी। इसी के साथ यूपी 'डिजिटल यूपी' में तब्दील होने वाला देश का पहला राज्य होगा।

ड्रोन से पूरे प्रदेश के एक-एक इलाके की हाई रेजोल्यूशन इमेज लेकर डिजिटल नक्शा बनाया जाएगा। इसका इस्तेमाल क्षेत्रों के बारे में सटीक डाटा तैयार करने, जीरो एरर लोकेशन जानने, जरूरत के हिसाब से योजना बनाने में किया जाएगा। इसके जरिये बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक स्थलों और उपयोगिताओं का भी डाटा तैयार होगा, ताकि आपदा या आपात स्थिति में तत्काल कार्ययोजना बनाई जा सके।

डिजिटल नक्शे से डिजास्टर मेनेजमेंट में जबर्दस्त लाभ मिलेगा। इसके अलावा भौतिक सर्वे से पहले ही लैंड यूज, विकास और पुल-सड़क-पुलिया आदि की सटीक क्रॉस चेकिंग हो सकेगी। नगर पंचायत, वार्ड का नक्शा से लेकर एक-एक घर का रिकार्ड भी डिजिटल सर्वे से तैयार किया जाएगा।

राजस्व बढ़ाने और करदाताओं की सहूलियत के लिए आनलाइन प्रापर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर,आनलाइन हाउस टैक्स साफ्टवेयर, वाटर टैक्स साफ्टवेयर और फैमिली साफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है ताकि घर बैठे टैक्स जमा करने के साथ पिछले रिकार्ड भी एक क्लिक में देखे जा सकें।

कितना पानी या बिजली इस्तेमाल की, इसकी ट्रैकिंग की सुविधा भी मिलेगी। प्रापर्टी सर्वेक्षण में संपत्ति का पूरा विवरण डिजिटल किया जाएगा, जिसमें मानचित्र से लेकर निर्माण तक की लाइव लोकेशन देखी जा सकेगी। ये भी पता चल जाएगा कि प्रापर्टी कामर्शियल, आवासीय या औद्योगिक में से किस श्रेणी की है।